



पंजीकृत

कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0)-द्वितीय

20 सरोजनी नायडू मार्ग 30प्र0, प्रयागराज

Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

पत्रांक- पेंशन विविध / DRY No.- 233, 240, 919, 2911

दिनांक :-

सेवा में,

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

समस्त कोषागार को ई-मेल द्वारा भेजा गया।

विषय :- अन्य राज्यों के राज्य कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत का भुगतान।

महोदय,

इस पत्र के साथ निम्नलिखित राज्यों से प्राप्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत सम्बन्धी शासनादेशों की प्रतियां प्रेषित कर रहा हूँ, जिसके अनुसार संबन्धित राज्य की पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि में मंहगाई राहत की दर एवं प्रभावी तिथि निम्नानुसार होगी :-

क्रमांक	राज्य का नाम	विषय / दर / प्रभावी तिथि	शासनादेश का सन्दर्भ
1	ODISHA	Dearness Relief (T.I) @ 04% enhancing the existing rate from 46% to 50% in favour of the State Government Pensioners/Family pensioners with effect from 01.01.2024	GO. No.- FIN-CS3-PEN-0002/2020/ 6633/F, Dated 14.03.2024
2	PUDUCHERRY	Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners / family pensioners Revised rate effective from 01.01.2024 (46% to 50%)	G.O Ms. No.- 74/FD/F3/ A2/ 2023-24, Dated 15.03.2024
3	TRIPURA	Grant of total quantum of Dearness Relief @20% w.e.f. 01/12/2022 and @ 25% w.e.f. 01/01/2024 over the basic Pension / basic family Pension to the Tripura Govt. Pensioners / family Pensioners.	1- G.O.- F.5(1)-FIN(PC) /2021/887-960, Dated 27.12.2022 2- G.O.- F.5(1)-FIN(PC) /2021/2046-2246, Dated 12/03/2024
4	JHARKHAND	झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में	G.O. No. - 13/वरीय विविध- 01/2024 का0 1459, दिनांक 27/02/2024

आपसे अनुरोध है कि संलग्न शासनादेशों में निहित निर्देशानुसार उक्त दरों से, संबन्धित राज्य के पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत का भुगतान देयता के आधार पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को भी सूचित करें। उक्त आदेशों की प्रति कोषागार के नोटिस बोर्ड में चस्पा करके व्यापक रूप से प्रचारित कर एवं अपने अधीनस्थ उप कोषागारों एवं बैंको को भी प्रति प्रेषित करें।

भवदीय

वरि० लेखाधिकारी / पेंशन

No. Pension(Misc)/

Dated :-

Copy forwarded for information and necessary action to:-

SL.	Name of the Office & Address
1	PAG(A&E) Odisha, Keshari Nagar, Bhuneshwar - 751001
2	The Directorate of Accounts & Treasuries D.A.T. Road, Rainbow Nagar. Puducherry - 605001
3	PA.G.(A&E)- Tripura, P.O.Kunjanban Agartala - 799006
4	PAG(A&E)- Jharkhand, North office Para, Shyamali Colony, Doranda Ranchi - 834002
5	Director of Treasuries, Jawahar Bhawan, 10 th Floor, Lucknow 226001
6	निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ -226001
7	Sr. Accounts Officer, O/o the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Audit Bhawan, Vibhuti Khand, Gomatinagar, Lucknow-226010.
8	Dy. Accountant General (Pension) Cell Local.
9	Sr. Accounts Officer, Computer Cell , O/o the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, 20 Sarojini Naidu Marg, Prayagraj-211001

वरि० लेखाधिकारी / पेंशन

8
EC 34389447111



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय
आडिट भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
Office of the Accountant General (A&E)-II. U.P.
Audit Bhawan, Vibhuti Khand,
Gomti nagar, Lucknow



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

पत्रांक: एसएसए-1/ 198

दिनांक: 2/4/24

सेवा में,

वर्गित लेखाधिकारी (पेंशन विविध)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) II

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

विषय: झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) झारखण्ड रांची द्वारा पत्र संख्या पेन-5/2023-24/55A-59/1829 दिनांक: 22/03/2024 प्राप्त हुआ है जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड के संकल्प संख्या 1459 दिनांक 27/02/2024 झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने से सम्बंधित है।

अतः इस कार्यालय का पत्र संख्या CD-1684 दिनांक 28/03/2024 आपको मूलरूप में संलग्नको सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-पत्र मूल रूप में

भवदीय

Signed by Krishna Kumar
Nigam

Date: 02-04-2024/141822.1



2917
4/4/24

कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं ह०) II,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

Pen (misc)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड का कार्यालय, राँची
OFFICE OF THE
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&E) JHARKHAND, RANCHI



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

पत्रांक पेन -5 / 2023-24 / 55A-59/-1829

दिनांक 22.03.2024

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) -II

उत्तर प्रदेश विभूती कांड, गान्धी नगर

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 226 010

विषय: झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रमाण: कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या 1459 दिनांक 27.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या 1459 दिनांक 27.02.2024 प्राप्त हुआ है, जो झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित है।

अतः उपरोक्त संकल्प की प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि उक्त संकल्प के अनुरूप विभिन्न भत्तों के भुगतान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश सभी संबंधित कोषागार को दिया जाय।

अनु: यथोपरी

भवदीय

स्वा. प्र. कुमार मिश्रा

वरीय लेखा अधिकारी

SJA-I
OD
Smt Rami
28/03/24

CD 16841
28/3/24

27/08/2024

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
संकल्प

विषय:- झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (सेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी अनुशंसाएँ एवं उक्त क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटिशन संख्या 1022/1989 (All India Judges Association Vs Union of India and Ors.) में दिनांक 06.12.2005 एवं 21.02.2006 को पारित आदेश के संदर्भ में झारखण्ड राज्य न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के सदस्यों को भत्ते/सुविधाएँ प्रदान करने के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या 4598 दिनांक 29.08.2006 निर्गत है।

2. द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा की गयी अनुशंसाओं एवं उक्त क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P.(Civil) No.643/2015, All India Judges Association Vs Union of India and Ors. मामले में दिनांक 04.01.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को भत्ते एवं सुविधाएँ निम्न रूप में देय होंगे :-

I. गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) :- झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को भारत सरकार के House Building Advance Rules, 2017 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त निजी व्यक्ति से Ready Build House क्रय करने की अनुमति अनुमान्य होगी।

अथवा

झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को Advance की सुविधा अनुमान्य होगी। राज्य सरकार के सरकारी सेवकों की भौति गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) की सुविधा अनुमान्य होगी।

II. बच्चों की शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance):- राज्य के प्रत्येक न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को शैक्षणिक वर्ष (Academic Year) 2019-20 के प्रभाव से निम्न रूपेण Children Education Allowance अनुमान्य होगा।

- (i) कक्षा 12 तक दो बच्चों की शिक्षा हेतु प्रति माह 2250.00 रु० शैक्षणिक भत्ता एवं प्रतिमाह 6750.00 रु० छात्रावास सब्सिडी अनुमान्य होगा।
- (ii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रतिपूर्ति उपर्युक्त उल्लेखित दर से दुगुनी होगी।
- (iii) महँगाई भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने पर भत्ते और सब्सिडी में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

जिन पदाधिकारियों को यह लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा है उनपर अनुशंसा का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

III. नगर प्रतिपूरक भत्ता (City Compensatory Allowance) - आसंग की अनुशरा के आलोक में नगर प्रतिपूरक भत्ता को समाप्त किया गया है परन्तु भुगतान किए गये नगर प्रतिपूरक भत्ते की वसूली संवर्धित पदाधिकारियों से नहीं की जायेगी।

IV. अतिरिक्त प्रभार भत्ता (Concurrent Charge Allowance)

- (i) राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का प्रतीकृत पद के कार्य के प्रभार में 10 कार्य दिवसों से अधिक कार्य तक वागस्त रहन तथा पर्याप्त न्यायिक कार्यों के संपादन करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त प्रभार के पद के न्यूनतम वेतनमान के दस प्रतिशत (10 प्रतिशत) के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमान्य होगा।
- (ii) न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा किये गये कार्यों की संख्या, न्यायिक कार्य की मात्रा एवं सम्पादित प्रशासनिक कार्यों के आधार पर अतिरिक्त प्रभार भत्ता देने का निर्णय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

V. वाहन/परिवहन भत्ता (Conveyance/Transport Allowance):- राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों के लिए पूर्व से निगंत आदेश को अवक्रमित करते हुए निम्नलिखित रूप से वाहन सुविधा/परिवहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) पुल कार की सुविधा को समाप्त की जाती है। राज्य में कार्यरत न्यायिक पदाधिकारी अपनी इच्छानुसार इस सुविधा को एक वर्ष या इससे अधिक समय तक के लिए जारी रख सकते हैं, परन्तु ऐसी स्थिति में उन्हें परिवहन भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

- (ii) न्यायिक पदाधिकारियों के स्वयं के वाहन के रख रखाव एवं चालक के वेतन हेतु प्रदान किया जाने वाले परिवहन भत्ता को दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से 10,000.00 ₹ से बढ़ाकर 13,500.00 ₹ प्रतिमाह किया जाता है। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2020 तक परिवहन भत्ता 10,000.00 रुपये की दर से अनुमान्य होगा।

वैसे न्यायिक पदाधिकारियों को सरकारी चालक या वाहन चालन जाननेवाले परिचारक/आदेशपाल आवंटित हैं, उन्हें प्रतिमाह 4,000 ₹ का परिवहन भत्ता अनुमान्य होगा।

- (iii) परिवहन भत्ता के अतिरिक्त, शहरों तथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1994/वि0 दिनांक-29.06.2010 एवं संकल्प संख्या-400/वि0 दिनांक-02.02.2017 के अनुसार 100 लीटर पेट्रोल/डीजल तथा अन्य क्षेत्रों में 75 लीटर पेट्रोल/डीजल के कीमत की प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी।

- (iv) प्रधान जिला न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/निदेशक, Judicial Academy/प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार को एक स्वतंत्र वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय उक्त सूची को कम कर सकती है।
- (v) न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा उपयोग में लाये जा रहे सरकारी वाहनों के सरकारी प्रायोजन को उनके द्वारा प्रमाणित किये जाने एवं लॉग बुक संधारित किये जाने की शर्त पर डीजल एवं पेट्रोल की वास्तविक खपत की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। न्यायिक पदाधिकारी प्रतिमाह 300 किलोमीटर सीमा के अन्दर निजी उद्देश्यों के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग कर सकेंगे।
- (vi) न्यायिक पदाधिकारियों को 10 लाख की सीमा तक Nominal Interest पर वाहन क्रय हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

VI. महँगाई भत्ता (Dearness Allowance):- राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप महँगाई भत्ता पूर्व से ही प्रदत्त है।

VII. अर्जित अवकाश नकदीकरण (Earned Leave Encashment):-

- A. राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों/वरीय न्यायिक पदाधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के समय 300 दिनों का अर्जित अवकाश नकदीकरण अनुमान्य होगा।
- B. राज्य के न्यायिक पदाधिकारी/वरीय न्यायिक पदाधिकारी नकदीकरण का हकदार होगा:-
- LTC का उपभाग करते समय 10 दिनों की अर्जित अवकाश, जो अधिकतम सीमा 60 दिनों के अधीन अनुमान्य होगा। पदाधिकारी अपने पूरे सेवाकाल में एक समय में 10 दिन तक यह सुविधा 06 बार प्राप्त कर सकेंगे।
 - 02 वर्षों के ब्लॉक में 30 दिन।
 - उपरोक्त (i) एवं (ii) के प्रावधान सेवानिवृत्ति के समय 300 दिनों के अर्जित अवकाश नकदीकरण के अतिरिक्त होगा।
- C. वैसे पदाधिकारियों जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके अवकाश नकदीकरण स्वीकृति के समय उनके द्वारा अपने सेवाकाल में किये गये Leave Encashment को समायोजित करते हुए समायोजित अर्जित अवकाश के भुगतान की कार्रवाई तीन माह के अंदर की जायेगी।

VIII. जल एवं विद्युत चार्ज (Water and Electricity Charges)

- (i) प्रतिपूर्ति के प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित 50 प्रतिशत का प्रतिपूर्ति Formula जारी रहगा।
- (ii) विद्युत इकाई एवं जल की मात्रा के उपयोग की सीमा निम्नवत् होगी:-

Designation	Electricity	Water Quantity
District Judges	8000 units per annum	420 Kls per annum
Civil Judges	6000 units per annum	336 Kls per annum

- (iii) यह प्रतिपूर्ति भुगतान किये गये विपत्रों को प्रस्तुत करने के उपरान्त त्रिमाही आधार पर की जायगी।
- (iv) बढे हुए भत्ते दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से देय होंगे।

IX. उच्च योग्यता भत्ता (Higher Qualification Allowance)

- (i) न्यायिक पदाधारियों को उच्च योग्यता अर्थात् कानून में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि तथा कानून में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने पर एक अतिरिक्त अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी।
- (ii) कानून में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट डिग्री के लिए प्रदत्त अग्रिम वेतन वृद्धि वैसी स्थिति में पदाधिकारी को दोबारा नहीं दी जायेगी, यदि भविष्य में वे किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं।
- (iii) अग्रिम वेतन वृद्धि उन्हीं पदाधिकारी को अनुमान्य होगी, जिसने या तो भर्ती से पहले या सेवा में रहने के बाद किसी भी समय में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की हो।
- (iv) यदि पदाधिकारी ने सेवा में भर्ती होने के पूर्व ही स्नातकोत्तर डिग्री या डॉक्टरेट प्राप्त कर ली है, तो अग्रिम वेतन वृद्धि प्रारम्भिक भर्ती की तिथि से अनुमान्य होगी। यदि पदाधिकारी के द्वारा यदि सेवा में भर्ती होने के बाद स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट डिग्री अर्जित की है, तो अग्रिम वेतन वृद्धि डिग्री अर्जित करने की तिथि से अनुमान्य होगी।
- (v) पदाधारियों को उच्चतर योग्यता के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि नियमित अध्ययन (पूर्णकालिक या अंशकालिक) या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से डिग्री प्राप्त करने की स्थिति में अनुमान्य होगी।
- (vi) अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ एसीपी चरण (ACP I या II) में भी अनुमान्य होगा। अग्रिम वेतन वृद्धि तब भी उपलब्ध होगी जब पदाधिकारी को सिविल

जज (जूनियर डिवाजन) से सावल जज (सीनियर डिवाजन) तथा सावल जज (सीनियर डिवाजन) से जिला जज कैडर में पदोन्नत किया जाता है।

(vii) अग्रिम वेतन वृद्धि जिला न्यायाधीश संवर्ग में जिला न्यायाधीश (Entry Level) से जिला न्यायाधीश (Selection Grade) तक और जिला न्यायाधीश (Selection Grade) से जिला न्यायाधीश (Super Time Scale) तक को अनुमान्य होगी।

(viii) अग्रिम वेतन वृद्धि वेतन का हिस्सा होगी और महंगाई भत्ता तदनुसार अनुमान्य होगी।

X. गृह अर्दली / घरेलू सहायता भत्ता (Home Orderly Help Allowance) :-

(i). न्यायिक पदाधिकारियों को गृह-सह-कार्यालय अर्दली भत्ता निम्न दर पर अनुमान्य होगा :-

(a) जिला न्यायाधीश :- राज्य में एक अकुशल मजदूर के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अनुमान्य दर से, जो प्रतिमाह 10,000.00 रु० से अन्यून होगा।

(b) सिविल जज - राज्य में एक अकुशल मजदूर के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का 60 प्रतिशत की दर से जो प्रतिमाह 7500.00 रु० से अन्यून होगा।

(ii). न्यायिक पदाधिकारियों को गृह-सह-कार्यालय अर्दली भत्ता दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से अनुमान्य होगा।

(iii). जिन न्यायिक पदाधिकारियों को आवासीय कर्तव्यों के लिए परिचारक / आदेशपाल / कार्यालय अधीनस्थ उपलब्ध कराया गया है, वे न्यायिक पदाधिकारी या तो वर्तमान प्रणाली को जारी रख सकते हैं या अनुशंसित भत्ते का त्याग कर सकते हैं या कार्यालय परिचारक / आदेशपाल की सेवा लेने की बजाय भत्ते का दावा करने का विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

(iv). न्यूनतम वेतन के समतुल्य समेकित वेतन पर नियुक्त गृह अर्दली / आवासीय परिचारक / सेवक का पैन्ल तैयार करते हुए उन्हें न्यायिक पदाधिकारियों को आवंटित करने का निर्णय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा किया जायेगा और ऐसे मामलों में गृह अर्दली भत्ते का दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(v). दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से घरेलू सहायता भत्ता पेंशनधारियों के लिए प्रतिमाह 9000.00 रु० तथा पारिवारिक पेंशनधारियों के लिए प्रतिमाह 7500.00 रु० अनुमान्य होगा। दिनांक-01.01.2016 से 05 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथा 01.01.2021 के प्रभाव से उक्त भत्ते में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी अनुमान्य होगी।

(vi). न्यायिक पदाधिकारी / पेंशनधारी / पारिवारिक पेंशनधारियों के स्वयं प्रमाणन (Self Certification) के पश्चात् ही भत्ता अनुमान्य होगा।

XI.

मकान किराया भत्ता एवं आवासीय क्वार्टर (House Rent Allowance & Residential Quarters) -

A. आवासीय क्वार्टर (Residential Quarters) -

- (i) प्रत्येक न्यायिक पदाधिकारी को उनकी पात्रता के अनुसार नियुक्त, सरकारी आवास भवन निर्माण विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा अथवा प्रभार ग्रहण के एक माह के अंदर उनकी माँग के अनुसार निजी आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- (ii) यदि न्यायिक पदाधिकारियों को एक महीने के भीतर सरकारी आवास या अपेक्षित निजी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वे निजी आवास निम्नलिखित शर्तों के अधीन ले सकते हैं :-
 - (a) यदि निजी आवास का किराया नीचे उल्लेखित अनुमान्य मकान किराया भत्ता के अंदर है तो किराया निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु संबंधित न्यायिक पदाधिकारी के द्वारा भुगतान किये जा रहे वार्षिक किराये को प्रमाणित करना होगा।
 - (b) यदि निजी आवास का किराया अनुमान्य मकान किराया भत्ता से अधिक है, तो किराये का मूल्यांकन HWA/R&B पदाधिकारियों की सहायता से प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।
 - (c) यदि अनुमान्य मकान किराया भत्ता और मूल्यांकन किये गये किराये के बीच का अन्तर 15 प्रतिशत से अधिक है तो प्रधान जिला न्यायाधीश उक्त राशि के भुगतान के लिए झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा प्राप्त करवा बशर्ते कि संबंधित न्यायिक पदाधिकारी अन्तर राशि का भुगतान करने के लिए तैयार न हो।

B. मकान किराया भत्ता (HRA) -

- (i) जिन न्यायिक पदाधिकारियों को सरकारी आवास आवंटित किया गया है, वे मकान किराया भत्ता के हकदार नहीं होंगे।
- (ii) ऐसे न्यायिक पदाधिकारी जो अपने आवास में निवास कर रहे हैं या माता-पिता या पति/पत्नी (जो लागू हों) के घर में निवास कर रहे हैं, वे उच्च न्यायालय से अपने घर में रहने की अनुमति प्राप्त करने के बाद 01.01.2016 के प्रभाव से अनुशंसित HRA के हकदार होंगे। साथ ही, ऐसे न्यायिक पदाधिकारी जो पहले से ही किराए के आवास में रह रहे हैं वे दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से अनुशंसित HRA के हकदार होंगे। भुगतान किया गया वास्तविक किराया उक्त सीमा के अधीन होगा।

- (iii) प्रधान जिला न्यायाधीश का कार्यालय या समकक्ष कार्यालय सीधे मकान मालिक को किराया मुमतान करेगा, ऐसी स्थिति में पदाधिकारी HRA प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (iv) राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को मकान किराया भत्ता राज्य सरकार के कमियों के अनुरूप (X श्रेणी 24%, Y श्रेणी 16% / श्रेणी 8%) पूर्व से ही देय है जो क्रमशः प्रतिमाह 5400, 3600 और 1800 रुपये से कम नहीं होगा।
- (v) महंगाई भत्ते में परिवर्तन होने पर न्यायिक पदाधिकारियों के लिए मकान किराया भत्ता में निम्नवत परिवर्तन होगा:-

Classification of Cities	Rates of HRA/pm as % of basic pay	When DA crosses
X	27%	25%
	30%	50%
Y	18%	25%
	20%	50%
Z	09%	25%
	10%	50%

C. फर्नीचर और एयर कंडीशनर भत्ता (Furniture and Air Conditioner Allowance):-

- (i) प्रत्येक न्यायिक पदाधिकारी को प्रत्येक पाँच वर्ष में क्रय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के शर्तों के अधीन 1.25 लाख रुपये का फर्नीचर अनुदान अनुमान्य होगा। उक्त अनुदान से घरेलू विद्युत उपकरण भी खरीदे जा सकते हैं।
- (ii) वैसे न्यायिक पदाधिकारी जिनकी सेवा दो वर्षों की हो चुकी है वे भी इस भत्ते के पात्र होंगे।
- (iii) पदाधिकारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे फर्नीचर को मूल्यह्रास दर पर खरीदने का विकल्प नए अनुदान या सेवानिवृत्ति के समय उपलब्ध होगा।
- (iv) फर्नीचर अनुदान के अलावा प्रत्येक न्यायिक पदाधिकारी के आवास पर प्रत्येक पांच वर्ष में एक एयर कंडीशनर प्रदान किया जाएगा।

1). आवासीय क्वार्टर रख रखाव (Maintenance):-

आवासीय क्वार्टरों के उचित रख रखाव हेतु झारखण्ड उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक प्रधान जिला न्यायाधीश को दस लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी और प्रस्ताव प्राप्त होने के दो माह के भीतर प्रस्तावित राशि की मंजूरी राज्य सरकार प्रदान करेगी।

XII. एल.टी.सी./एच.टी.सी. (LTC/HTC) :- न्यायिक पदाधिकारियों के लिए एल.टी.सी. एवं एच.टी.सी. के अधीन निम्न सुविधाएँ अनुमान्य होंगी --

(i) LTC की सुविधा का उपभोग नहीं करने पर एक माह के वेतन का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

(ii) LTC (HTC नहीं) का उपभोग करने की स्थिति में 10 दिनों का अर्जित अवकाश का नगदीकरण अनुमान्य होगा जिसकी अधिकतम सीमा 60 दिनों की होगी। यह सेवानिवृत्ति के समय 300 दिन और दो साल के ब्लॉक में 30 दिन के नगदीकरण के अतिरिक्त होगा।

iii(a) LTC की आवृत्ति के संबंध में, न्यायिक पदाधिकारियों को 3 साल के ब्लॉक में एक LTC और एक HTC अनुमान्य होगा।

iii(b) नव नियुक्त न्यायिक पदाधिकारियों को 3 साल के पहले ब्लॉक में 2 बार LTC अनुमान्य होगा। उनका लिए 3 साल का ब्लॉक परीक्षा के लिए निर्धारित अवधि के पूर्ण होने पर शुरू होगा।

iv(a) न्यायिक पदाधिकारियों को उनकी कांटे के आधार पर हवाई यात्रा अनुमान्य होगी और प्रतिपूर्ति इस शर्त के अधीन की जाएगी कि टिकट या तो सीधे एयरलाइंस से या केंद्र/राज्य सरकार के अधिकृत एजेंटों अर्थात् अशोक ट्रेवल्स, बामर एवं लॉरी और आई.आर.सी.टी.सी. से खरीदे गए हों।

iv(b) अन्य विवरण जैसे यात्रा की श्रेणी, अग्रिम आदि राज्य से निर्गत नियमों/आदेशों से शासित होंगे।

(v) न्यायिक पदाधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए भारत में कहीं भी LTC को आगे बढ़ाने की सुविधा अनुमान्य होगी।

(vi) सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को LTC/HTC की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

(vii) न्यायिक पदाधिकारियों का LTC/HTC प्रयोजन के लिए केवल अर्जित अवकाश का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें दो दिनों की सीमा तक prefix और suffix के साथ आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने की भी अनुमति होगी।

- (i) राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से रु0 3000/- प्रति माह तय चिकित्सा भत्ता अनुमान्य होगा।
- (ii) पेशनधारी एवं परिवारिक पेशनधारियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से रु0 4000/- प्रति माह तय चिकित्सा भत्ता अनुमान्य होगा।

XIV. समाचार पत्र/पत्रिका भत्ता (Newspaper and Magazine Allowance):-

- (i) राज्य के सभी जिला न्यायाधीशों को दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से दो समाचार पत्रों एवं दो पत्रिकाओं की प्रतिपूर्ति हेतु 1000.00 रु0 तथा सिविल जजों को दो समाचार पत्रों एवं एक पत्रिका की प्रतिपूर्ति हेतु 700.00 रु0 अनुमान्य होगा।
- (ii) प्रतिपूर्ति स्वयं प्रमाणन (Self Certification) पर अर्द्धवार्षिक आधार पर (जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसम्बर) की जायेगी।

XV. पोशाक भत्ता (Robe Allowance) :- झारखण्ड राज्य में कार्यरत न्यायिक पदाधिकारियों के लिए दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से प्रत्येक 03 वर्ष पर 12,000.00 रु0 का पोशाक भत्ता अनुमान्य होगा।

XVI. प्रशासनिक कार्यों के लिए विशेष वेतन (Special Pay for Administrative work):- न्यायिक पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक कर्तव्यों के निष्पादन हेतु दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से निम्न रूप से विशेष वेतन अनुमान्य होगा:-

a	Principal District and Sessions Judges	Rs.7000/- per month
b	Other District Judges including 1 Additional District Judges entrusted with administrative work who have to generally spend time beyond Court working hours	Rs. 3500/- per month.
c	District Judges presiding over Special Courts and Tribunals having independent administrative responsibilities	Rs.3500/- per month.
d	CJMs and Principal Senior, Junior Civil Judges and other Judicial Officers having administrative responsibilities being in charge of independent Courts with filing powers	Rs.2000/- per month.

XVII. आतिथ्य भत्ता (Sumptuary Allowance) :-

- (i) राज्य के सभी जिला न्यायाधीशों को प्रतिमाह 7800/- रुपये, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को 5800/- रुपये एवं सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को 3800/- रुपये दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से आतिथ्य भत्ता अनुमान्य होगा।

- (ii) जिलों में पशारनिक कार्यों के प्रभावी प्रधान जिला न्यायाधीश/संलग्नक ग्रेड एवं सुपर टाईम स्कैन के जिला न्यायाधीश/निदेशक, न्यायिक अकादमी/न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान/सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार/मुख्य न्यायिक दफ्तराधिकारी का अतिरिक्त कर्तव्यों के निर्वहन हेतु 1000/- रुपये का अतिरिक्त आतिथ्य भत्ता अनुमान्य होगा।

XVIII. दूरभाष सुविधा (Telephone Facility) :-

- (i) न्यायिक पदाधिकारियों को उनके आवास पर निम्नरूपेण Landline एवं Broadband (सभी दर कॉल (लोकल एवं STD) एवं इन्टरनेट सहित) की सुविधा अनुमान्य होगी -

1	जिला न्यायाधीश	1500/- रु0 प्रतिमाह	1000/- रु0 प्रतिमाह (Broadband की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में)
2	सिविल जज	1000/- रु0 प्रतिमाह	750/- रु0 प्रतिमाह (Broadband की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में)

- (ii) न्यायिक पदाधिकारियों को मोबाइल फोन (Handset) के क्रय एवं इन्टरनेट की सुविधा निम्नरूपेण अनुमान्य होगी -

क्र0	न्यायिक पदाधिकारी	मोबाइल फोन (Handset) केय की राशि	मोबाइल फोन (इन्टरनेट डाटा सहित) के उपयोग हेतु वॉल सीमा
1	जिला न्यायाधीश	30,000/- रु0	2000/- रु0 प्रतिमाह
2	सिविल जज	20,000/- रु0	1500/- रु0 प्रतिमाह

- (iii) न्यायिक पदाधिकारियों के अनुरोध पर प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार मोबाइल फोन (Handset) बदलने की सुविधा उपलब्ध होगी।

- (iv) न्यायिक पदाधिकारियों के पास पुराने Mobile Handset का माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रजिस्ट्री के द्वारा मूल्य निर्धारित करते हुए Retain करने का विकल्प होगा।

- (v) वर्तमान में कार्यालय में उपलब्ध दूरभाष की सुविधा यथावत् रहेगी।

XIX. स्थानान्तरण अनुदान (Transfer Grant) :-

- (i) न्यायिक पदाधिकारियों के स्थानान्तरण पर समग्र स्थानान्तरण अनुदान (Composite transfer grant) एक माह के मूल वेतन के समतुल्य अनुमान्य होगा।

- (ii) राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को 20 किलोमीटर या उससे कम या उसी शहर में स्थानान्तरण होने की स्थिति (आवास के वास्तविक परिवर्तन होने पर)

में उन्हें एक माह के मूल वेतन का 1/3 स्थानान्तरण अनुदान अनुमान्य होगा।

- (iii) निजी सामग्रियों के परिवहन के लिए सातवें CPC द्वारा किये गये अनुशंसाओं के अनुरूप वित्त विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत O.M. दिनांक 13.07.2017 द्वारा निर्धारित दर अनुमान्य होगा।
 - (iv) सड़क के माध्यम से परिवहन की स्थिति में प्रति किलोमीटर 50 रु की दर (सामग्रियों के loading/unloading हेतु मजदूरी सहित या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो) से स्थानान्तरण अनुदान अनुमान्य होगा। महँगाई भत्ता के 50 प्रतिशत होने की स्थिति में उक्त दर में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
 - (v) उपर्युक्त अनुदान दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से प्रभावी होगा।
 - (vi) वैसे न्यायिक पदाधिकारी जिनका स्थानान्तरण दिनांक 01.01.2016 के बाद हुआ है और उनके द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के पूर्व स्थानान्तरण अनुदान का दावा किया गया है, उन्हें पुनरीक्षित वेतन के आधार पर अन्तर राशि का भुगतान किया जायेगा।
3. कंडिका- 2(I) में वर्णित गृह अग्रिम की राशि का भुगतान व्यय शीर्ष 7610-सरकारी सेवकों आदि को उधार लघु शीर्ष 201-गृह निर्माण अग्रिम उप शीर्ष-01 सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम विस्तृत शीर्ष 07 के अधीन-63 गृह निर्माण अग्रिम मद से किया जायेगा। कंडिका-2(XII) में अंकित LFC भत्ता का भुगतान विस्तृत शीर्ष-01 वेतन एवं भत्ते के अधीन-12 छुट्टी यात्रा रियायत मद से किया जायेगा। कंडिका-2(XIX) में अंकित स्थानान्तरण अनुदान का भुगतान, विस्तृत शीर्ष-02 यात्रा भत्ते के अधीन-13 देशीय यात्रा व्यय मद से किया जायेगा। शेष सभी भत्तों का भुगतान, विस्तृत शीर्ष-01 वेतन एवं भत्ते के अधीन-01 वेतन मद से किया जायेगा।
4. झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों/सुविधाएँ के संबंध में पूर्व से निर्गत संकल्प/नियम/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
5. प्रस्ताव पर मन्त्रिपरिषद् की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक-1078, दिनांक 13.02.2024 के क्रम में दिनांक 23.02.2024 की बैठक के मद संख्या-20 के रूप में दी गयी है।
- आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

Pranveer
27/02/24
(प्रवीण कुमार टोप्पो)
सरकार के सचिव

ज्ञापक:-13/वरीय विविध-01/2024 का0.....11.11.24.....राँची, दिनांक.....27/02/24

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव-सह-भाडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई-गजट में प्रकाशनाथ प्रेषित।

fauzan
27/02/24

सरकार के सचिव।

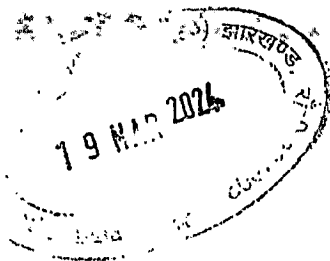
ज्ञापक:-13/वरीय विविध-01/2024 का0.....11.11.24.....राँची, दिनांक.....27/02/24

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, उर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, पेयजल एवं स्वाच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव-विधि-परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कोषाग, झारखण्ड/महासचिव, झारखण्ड, राँची/महानिबधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची/सचिव न आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ।

fauzan
27/02/24

सरकार के सचिव।

OK



SP
EO 261826365 IN

15/3/24



OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL(A & E),
ODISHA: BHUBANESWAR-751001.

No.P.M/SS/F-28/2023-24/2310(34).

Dated-15/03/2024

To

1. THE PRINCIPAL ACCOUNTAT GENERAL (A&E), ANDHRA PRADESH, VIJAYAWADA-520002
2. THE DIRECTOR OF AUDIT & PENSION, GOVERNMENT OF ARUNACHAL PRADESH, NAHARLAGUN-791110.
3. THE ACCOUNTAT GENERAL (A&E), ASSAM, GUWAHATI, MAIDAMGAON, BELTOLA, GUWAHATI-781029.
4. THE ACCOUNTAT GENERAL (A&E)-II, BIHAR, PATNA, BIRCHAND PATEL PATH, PATNA-800001.
5. THE ACCOUNTAT GENERAL (A&E), CHHATTISGARH, 12/27, RAMAN MANDIR WARD, BILASPUR ROAD, FAFADIH, RAIPUR-492009.
6. THE DEPUTY DIRECTOR OF ACCOUNTS/P.A.I. GOVT. OF GOA, DIRECTORATE OF ACCOUNTS, PENSION SECTION, PANAJI, GOA-403001
7. THE ACCOUNTAT GENERAL (A&E), GUJURAT, AHMEDABAD BRANCH, AUDIT BHAVAN, NAVARANGPURA, AHMEDABAD-380009.
8. THE ACCOUNTAT GENERAL (A&E), HARYANA, LEKHA BHAWAN, PLOT NO-4 & 5, SECTOR 33-B, CHANDIGARH-160047.
9. THE ACCOUNTAT GENERAL (A&E), HIMACHAL PRADESH, GORTON CASTLE BUILDING, SHIMLA-171003.
10. THE PRINCIPAL ACCOUNTAT GENERAL (A&E), JAMMU & KASHMIR, NEAR EXHIBITION GROUND, SRINAGAR-190009.
11. THE ACCOUNTAT GENERAL (A&E), JHARKHAND, PO-DORANDA, RANCHI-834002.
12. THE PRINCIPAL ACCOUNTAT GENERAL (A&E), KARNATAKA, RESIDENCY PARK ROAD, POST BOX NO. 5329/5369, BANGALORE-560001.
13. THE ACCOUNTAT GENERAL (A&E), KERALA, POST BOX NO: 5607, M.G. ROAD, THIRUVANANTHAPURAM-695039.
14. THE ACCOUNTAT GENERAL (A&E)-II, MADHYA PRADESH, LEKHA BHAVAN, JHANSI ROAD, GWALIOR-474002.
15. THE PRINCIPAL ACCOUNTAT GENERAL (A&E)-I, MAHARASHTRA, 2ND FLOOR, PRATISHTHA BHAVAN, NEW MARINE LINES, 101, MAHARSHI KARVE ROAD, MUMBAT-400020.

20 MAR 2024

Pen/mise

16. THE ACCOUNTANT GENERAL (A&I)-II. MAHARASHTRA, WEST HIGH COURT CIVIL LINES, NAGPUR-440001.
17. THE SENIOR DEPUTY ACCOUNTANT GENERAL (A&E), MANIPUR, IMPHAL-795001.
18. THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), MEGHALAYA, SHILLONG-793001.
19. THE CHIEF CONTROLLER OF ACCOUNTANTS, ACCOUNTS & TREASURY, GOVERNMENT OF, MIZORAM, MINECO, KHATLA, AIZAWL-796001.
20. THE SENIOR DEPUTY ACCOUNTANT GENERAL (A&E), NAGALAND, KOHIMA-797001.
21. THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), PUNJAB & UNION TERRITORY OF CHANDIGARH, SECTOR 17-E, CHANDIGARH-160017.
22. THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN, BHAGWAN DAS ROAD, JAIPUR-302005.
23. THE SENIOR DEPUTY ACCOUNTANT GENERAL (A&E), SIKKIM, LEKHA PARIKSHA BHAVAN, DEORALI, PO-TADONG, GANGTOK-737102.
24. THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), TAMIL NADU, 361, ANNA SALAI, TIRYNAMPET, CHENNAI-600018.
25. THE SENIOR DEPUTY ACCOUNTANT GENERAL (A&E), TRIPURA, PO-KUNJABAN, AGARTALA-799006.
26. THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), TELANGANA, HYDERABAD-500004.
27. THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, UTTAR PRADESH, 20, SAROJINI NAIDU MARG, ALLAHABAD-211001.
28. THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), UTTARAKHAND, DEHRADUN, OBEROY MOTOR BUILDING, SAHARANPUR ROAD, MAJRA, DEHRADUN-248171.
29. THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), WEST BENGAL, TREASURY BUILDINGS, NO. 2, GOVT. PLACE (WEST), KOLKATA-700001.
30. THE DIRECTOR OF ACCOUNTS AND TREASURIES, GOVT. OF PUDUCHERRY, PUDUCHERRY-605001.
31. THE PRINCIPAL CHIEF CONTROLLER OF ACCOUNTS, MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS, 3RD FLOOR, AKBAR BHAWAN, CHANAKYAPURI, NEW DELHI-110021.
32. THE OFFICER ON SPECIAL DUTY (PEN), GOVT. OF INDIA, MINISTRY OF FINANCE, DEPARTMENT OF EXPENDITURE, C.P.A.O. TRIKOOT-II, BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-110066.
33. THE PAY & ACCOUNTS OFFICER (V), DELHI ADMINISTRATION, TIS HAZARI, NEW DELHI-110124.
34. THE PRINCIPAL ACCOUNTS OFFICER, D.A 'B' BLOCK, VIKASHI BHAVAN, NEW DELHI.

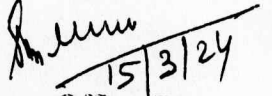
:- Sanction of Dearness Relief (TI) @ 04% enhancing the existing rate from 46% to 50% w.e.f.01/01/2024 in favour of the State Government pensioners/family pensioners vide Government of Odisha Finance Department O.M. No.FIN-CS3-PEN-0002/2020/6633/F dated 14/03/2024.

Sir.

I am to forward herewith Government of Odisha, Finance Department O.M. No.FIN-CS3-PEN-0002/2020/6633/F dated 14/03/2024 on the subject cited above, under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all Pension Disbursing Authorities under your jurisdiction.

Encl :- As above.

Yours faithfully


15/3/24
Sr.Accounts Officer/PM

GOVERNMENT OF ODISHA
FINANCE DEPARTMENT

No. FIN-CS3-PEN-0002-2020/ 6633 /F, Date: 14/03/2024

OFFICE MEMORANDUM

18 MAR 2024

Sub:- Sanction of Dearness Relief (T.I) @ 4% enhancing the existing rate from 46% to 50% in favour of the State Government pensioners/ family pensioners with effect from 01.01.2024.

Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions in their O.M.No.F-No.42/07/2022-P&PW(D) dated 13.03.2024 have enhanced the Dearness Relief admissible to the Central Government pensioners/family pensioners from the existing rate of 46% to 50% of the basic pension family pension (including additional pension/ family pension with effect from 01.01.2024.

2. In the meantime, one dose of Dearness Allowance @4% has been sanctioned in favour of the State Government employees enhancing Dearness Allowance from 46% to 50% with effect from 01.01.2024 vide Finance Department Office Memorandum No 6619/F, dated 14.03.2024.

3. After careful consideration of the matter, the State Government have been pleased to decide that Dearness Relief (T.I) on pension/ family pension shall be paid to the State Government pensioners/ family pensioners at the same rate of 4% on the revised basic pension/ family pension and provisional pension with effect from 01.01.2024. With sanction of one dose of Dearness Relief (T.I) at the rate of 4%, the Dearness Relief now payable on the revised basic pension/ family pension and provisional pension will be enhanced from 46% to 50% with effect from 01.01.2024.

4. The additional dose of Dearness Relief shall also be admissible on additional basic pension/ additional family pension available to the old pensioners/ family pensioners based on their age as indicated in this Department O.M. No.28300/F dated 23.09.2017.

For the purpose of this Office Memorandum

1. Pension/family pension in the case of the pre-01.01.2016 retirees and where family pension was due prior to 01.01.2016 means the revised basic pension/revised basic family pension as the case may be in terms of Finance Department Office Memorandum No.28300/F dated 23.09.2017.

**GOVERNMENT OF ODISHA
FINANCE DEPARTMENT**

No. FIN-CS3-PEN-0002-2020/ 6633 /F, Date: 14/03/2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Sanction of Dearness Relief (T.I) @ 4% enhancing the existing rate from 46% to 50% in favour of the State Government pensioners/ family pensioners with effect from 01.01.2024.

Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions in their O.M.No.F-No.42/07/2022-P&PW(D) dated 13.03.2024 have enhanced the Dearness Relief admissible to the Central Government pensioners/family pensioners from the existing rate of 46% to 50% of the basic pension family pension (including additional pension/ family pension with effect from 01.01.2024.

2. In the meantime, one dose of Dearness Allowance @4% has been sanctioned in favour of the State Government employees enhancing Dearness Allowance from 46% to 50% with effect from 01.01.2024 vide Finance Department Office Memorandum No 6619/F, dated 14.03.2024.

3. After careful consideration of the matter, the State Government have been pleased to decide that Dearness Relief (T.I) on pension/ family pension shall be paid to the State Government pensioners/ family pensioners at the same rate of 4% on the revised basic pension/ family pension and provisional pension with effect from 01.01.2024. With sanction of one dose of Dearness Relief (T.I) at the rate of 4%, the Dearness Relief now payable on the revised basic pension/ family pension and provisional pension will be enhanced from 46% to 50% with effect from 01.01.2024.

4. The additional dose of Dearness Relief shall also be admissible on additional basic pension/ additional family pension available to the old pensioners/ family pensioners based on their age as indicated in this Department O.M. No.28300/F dated 23.09.2017.

For the purpose of this Office Memorandum

- i. Pension/family pension in the case of the pre-01.01.2016 retirees and where family pension was due prior to 01.01.2016 means the revised basic pension/revised basic family pension as the case may be in terms of Finance Department Office Memorandum No.28300/F dated 23.09.2017.

No.DAT/Pen-I/A1/D.R1-24/2024

Puducherry, dated 15/03/2024

To

1. The Chief Controller (Pensions), Central Pension Accounting Office, GOI, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Trikot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110 066.
2. The Accounts Officer (Tech), Principal Accounts Office, Govt. of NCT of Delhi, 'A' Block, Vikas Bhawan, New Delhi.
3. The Accounts Officer, O/o the Accountant General (A&E), Tamil Nadu No.361, Anna Salai, Teynampet, Chennai 600018 / Kerala MR Road, Thiruvananthapuram 695001/ Karnataka Park House Road, Near Vidhnana Soudha, Bengaluru, Karnataka 560 0012. / Gujarat- Race Course Road, Rajkot /Andhra Pradesh / Himachal Pradesh / Rajasthan / West Bengal -8, Kiran Shankar Ray Road, BBD Bagh, Kolkata - 700001 / Maharashtra- Civil Lines, Nagpur.
4. The Deputy Accountant General (Pension), O/o. Accountant General (A&E) II UP, 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad - 211 001.
5. The Assistant General Manager, State Bank of India (CPPC), No.112/4, Kalliamman Koil Street, Virugambakkam, Chennai - 600 092.
6. The Assistant General Manager, Central Pension Processing Section, Indian Bank Main (Banking Operation Division), Second Floor, No.7, Pragasa Salai (Opp. To Panakal Park), T.Nagar, Chennai - 600017.
7. The Chief Manager, Centralised Pension Processing Centre, Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai - 600 002.
8. The Asst. General Manager, UCO Bank (CPPC), Somalwar Bhavan, Mount Road Extension, Nagpur, Maharashtra - 440 001.
9. The Manager, State Bank of India / Indian Overseas Bank / Indian Bank / UCO Bank, Puducherry / Karaikal/Mahe/Yanam.
10. The Pay & Accounts Officer - V, O/o the Pay & Accounts Officer, No.V (Pension), Govt. of National Capital Territory of Delhi, Tis Hazari, Delhi.
11. The Defence Attache, Indian Embassy Nepal, Military Pension Branch, Kathmandu, Nepal.
12. The Treasury / Sub-Treasury Officer, Puducherry / Karaikal / Villianur / Bahour / Mahe / Yanam.

Sir,

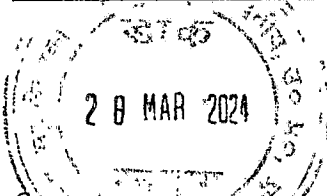
Sub: Grant of Dearness Relief to Pensioners and Family Pensioners of Union Territory of Puducherry - Revised rates effective from 01/01/2024 - Reg.

The Government of India have enhanced the existing rate of Dearness Relief on Pension / Family Pension from 46% to 50% of the Basic Pension/ Family Pension (including additional pension/family pension) with effect from 01/01/2024 in O.M.No.42/02/2024-P&PW(D), dated 13/03/2024 of the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare, New Delhi, with a condition that the payment of arrears of Dearness Relief shall not be made before the date of disbursement of pension/ family pension of March, 2024.

2. The Government of Puducherry has communicated the Orders of Government of India for extending the revised rate of Dearness Relief @ 50% with effect from 01/01/2024 to the Pensioners / Family Pensioners of the Union Territory of Puducherry vide G.O. Ms. No.74/ FD/F3/ A2/2023-24, dated 15/03/2024 of the Finance Department, Puducherry.

3. On the basis of the above orders, I am to authorize to effect payment of Dearness Relief at the revised rate of 50% as mentioned above with effect from 01/01/2024 to all eligible Pensioners / Family Pensioners of Union Territory of Puducherry drawing Pension from the Banks / Treasuries / Sub-Treasuries under your control subject to conditions governing the payment of Dearness Relief on Pension/ Family Pension as detailed in the Government of India Office Memorandum aforesaid.

4. The payment of arrears of Dearness Relief for the period from 01/01/2024 to 29/02/2024 shall not be made before the date of disbursement of Pension/ Family Pension of March, 2024.



240-
17/4/24
Pen (m)gc

Yours faithfully,

(S. PRABAVADY)
DIRECTOR

Copy to:

1. The Under Secretary to Government, Finance Department (F3), Puducherry.
2. The Programmer, EDP Section, DAT, Puducherry (To host in the official website).

No. 42/02/2024-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Date :- 13th March, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.01.2024-rcg

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/04/2023-P&PW(D) dated 27.10.2023 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of 46% to 50% of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) w.e.f 01st January, 2024.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

- (i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D) Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.
- (ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.
- (iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners.
- (iv) Railway Pensioners/Family Pensioners.
- (v) Pensioners who are in receipt of provisional pension.
- (vi) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners and Pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. The payment of arrears of Dearness Relief shall not be made before the date of disbursement of pension/family pension of March, 2024.

5. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021 and this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

Contd/....

6. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

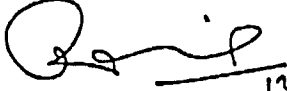
7. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

8. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of Dearness Relief to Pensioners/Family Pensioners on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

9. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

10. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/1/2024-E-II (B) dated 12.03.2024.

Hindi version will follow.


(Ravinder Kumar) 13/3/24
Director

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

//Copy//


(A. IDAYAVENDANE ANNIBAL)
Superintendent
Finance Department
Puducherry

GOVERNMENT OF PUDUCHERRY

Abstract

Finance Department - Grant of Dearness Relief to the Union Territory Government Pensioners/Family Pensioners - Revised rate effective from 01.01.2024 - Orders -Issued.

FINANCE DEPARTMENT

G.O.Ms.No.74/FD/F3/A2/2023-24

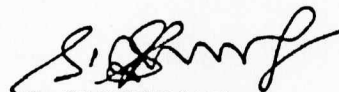
Puducherry, the 15.03.2024

Read: Office Memorandum No.42/02/2024-P&PW(D) dated 13.03.2024 of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Pension & Pensioners' Welfare, New Delhi .

ORDER:

1. Recorded.
2. A copy of the Office Memorandum read above is forwarded herewith for information and implementation with effect from 01.01.2024.

// BY ORDER //


(S. SIVAKUMAR)

UNDER SECRETARY TO GOVERNMENT(FINANCE)

Encl.: As stated.

To

All Secretariat Departments.

All Heads of Department/Office in Puducherry/Karaikal/Mahe and Yanam.

Copy to:

1. The Director of Accounts and Treasuries, Puducherry
2. The Sr. Dy. Accountant General, Puducherry Branch, Kumarakurupallam, Puducherry.
3. The Dy. Director of Accounts and Treasuries, Karaikal, Mahe and Yanam.
4. The Central Records Branch, Puducherry.
5. The Director, Information & Technology Department, Puducherry
- for uploading the G.O. in the State Portal.
6. The Web Site of Finance Department.
7. Stock File.

42848213624

Speed Post under Special Seal



प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (हक एवं लेखा), त्रिपुरा: अगरतला

OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
TRIPURA, AGARTALA - 799006

दूरभाष/Phone-0381-2353905, फैक्स /Fax- 0381-2350103,

ई-मेल/E-mail: agatripura@cas.gov.in



No.Pen-1/Tripura Relief/2023-24/ 17907 - 946

Date :

20 MAR 2024

To

The Pr. Accountant General(A&E),

(As per mailing list)

Subject Grant of total quantum of Dearness Relief @ 20% w.e.f. 01.12.2022 and @25% w.e.f. 01/01/2024 over the basic pension/basic family pension to the Tripura Government Pensioners/Family Pensioners.

Sir,

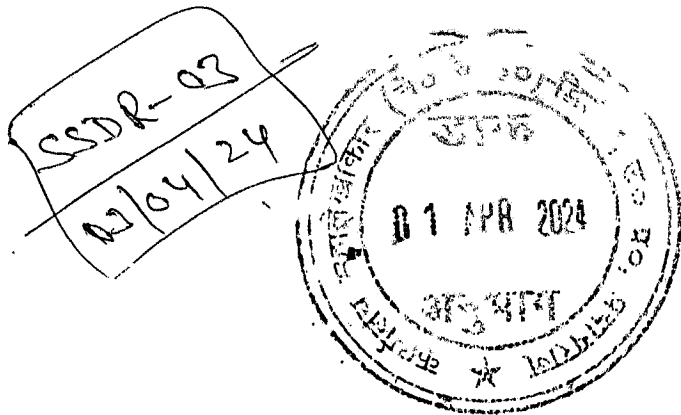
I am to enclose herewith copies of the Memorandum No F.5(1)-FIN(PC)/2021/887-960 dated 27th December, 2022 regarding grant of total quantum of Dearness Relief @20% and Memorandum No F.5(1)-FIN(PC)/2021/2046-2246 dated 12th March 2024 regarding grant of total quantum of Dearness Relief @25% w.e.f. 01/01/2024 over the basic pension/basic family pension to the Tripura Government Pensioners/Family Pensioners issued by the Finance Department, Government of Tripura.

You are, therefore, requested to make necessary arrangement to circulate those to all the Treasury Officers/Sub-Treasury Officers and Public Sector Banks under your jurisdiction to make payment.

Yours faithfully,

Encls : As stated.

Sr. Accounts Officer



कार्यालय महालेखाकार (हक एवं लेखा)-II,
अग्र, अगरतला

हाथी नं. 919
21/4/24
Pen/mise

Shri Mishra

1/8
02/04/24

Pen-1

GOVERNMENT OF TRIPURA
DEPARTMENT OF FINANCE
AGARTALA : TRIPURA

F.5(1)-FIN(PC)/2021/ 2046-2246

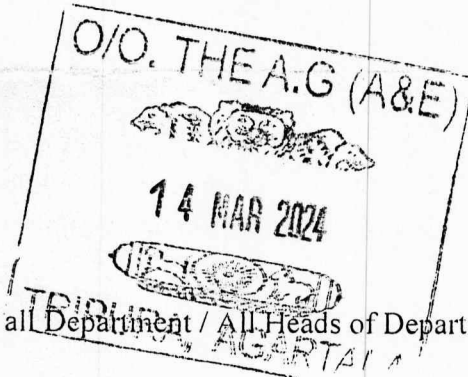
Agartala, 12th March, 2024

MEMORANDUM

Subject: Release of further installment of Dearness Relief.

The undersigned is directed to refer to the subject mentioned above and to state that the Governor of Tripura is pleased to decide grant of further installment of Dearness Relief @ 5% over the basic pension/ basic family pension as admissible under Tripura State Civil Services (Revised Pension) Rules, 2017 read with its 1st Amendment, 2018, with effect from 01-01-2024 to the State Government pensioners and family pensioners. With the release of this installment, total quantum of Dearness Relief payable to the State government pensioners and family pensioners with effect from 01-01-2024 shall stand at 25 % (20 % + 5 %) over the basic pension/ family pension, as the case may be.

2. The payment on account of Dearness Relief involving fractions of 50 paisa and above may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paisa may be ignored.
3. The Pension Disbursing Authorities including Public Sector Banks handling disbursement of pension/ family pension to the State Government Pensioners / Family Pensioners are authorized to calculate and disburse Dearness Relief at the above rate and manner in each individual case from 01-01-2024.
4. The expenditure on payment of Dearness Relief on pension/ family pension to the State Government Pensioners / Family Pensioners respectively shall be debitable to the Major Head '2071-Pension and other Retirement Benefits'.



To
Secretary In-charge of all Department / All Heads of Department.

(N. C. Majumder)
Under Secretary to the
Government of Tripura
Finance Department

Continued on page-2

Copy forwarded to :

1. The Secretary to the Hon'ble Governor of Tripura, Agartala.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Tripura, Agartala.
3. The PS/PA to all Hon'ble Ministers, Tripura.
4. The PS/PA to the Chief Secretary, Tripura, Agartala.
5. The Secretary, Tripura Legislative Assembly, Agartala.
6. The Secretary, T.P.S.C., Agartala.
7. The Account General (A&E), Tripura, Agartala with 5(five) ink signed copies.
8. The Accountant General (Audit), Tripura, Agartala with 5(five) ink signed copies.
9. The Accountant General of all States, _____
10. The Principal Chief Accountant, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government & Bank Accounts Administration, Division C & 7 Bandra Kurla Complex, 2nd Floor, Post Bag No.1843, Bandra (E), Mumbai-400 051.
11. The Chief Manager, Centralised Pension Processing Centre, State Bank of India, Zonal Office, Sethi Trust Building, Unit - I, 6th Floor, Bhangarh, Guwahati, Assam - 781005 for information and with request to arrange for sending a copy to each of their Bank Branches within the State of Tripura.
12. The General Manager, (Accounts, Govt. Transaction & IBR), Punjab National Bank, United Tower, Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001 for information and with request to arrange for sending a copy to each of their Bank Branches within the State of Tripura.
13. The Assistant General Manager, UCO Bank, Operation & Services Department, 3 & 4 DD Block, Sector - I, Salt Lake, Kolkata - 700064 for information and with request to arrange for sending a copy to each of their Bank Branches within the State of Tripura.
14. The Regional Manager (Urban), State Bank of India, Palace Compound, Jagannathbari Road, Agartala for information and with request to arrange for sending a copy to each of their Bank Branches within the State of Tripura.
15. The Regional Manager (Rural), State Bank of India, Bijoy Kumar Chowmuhani, Agartala for information and with request to arrange for sending a copy to each of their Bank Branches within the State of Tripura.
16. The Regional Manager, Punjab National Bank, Circle Office, Lakshminarayanbari Road (Near Durgabari), Agartala for information and with request to arrange for sending a copy to each of their Bank Branches within the State of Tripura.


12.03.2021

Continued on page-3

17. The Chief Manager, UCO Bank, Central Road, Kaman Chowmuhani, Agartala for information and with request to arrange for sending a copy to each of their Bank Braches within the State of Tripura.
18. The Joint Secretary, Establishment-I Branch, Finance Department, Agartala.
19. All Treasury / Sub-Treasury Officers, Tripura _____
20. The Joint Director, Department of Information Technology for uploading this Memorandum in the State Government Website.
21. The Web Administrator, Finance Department for uploading this Memorandum in the web-portal of Finance Department.


2.03.2024
(N. C. Majumder)
Under Secretary to the
Government of Tripura
Finance Department

GOVERNMENT OF TRIPURA
DEPARTMENT OF FINANCE
AGARTALA : TRIPURA

F.5(1)-FIN(PC)/2021/887-960

Agartala, 27th December, 2022

MEMORANDUM

Subject: Release of further installment of Dearness Relief.

The undersigned is directed to refer to the subject mentioned above and to state that the Governor of Tripura is pleased to decide grant of further installment of Dearness Relief @ 12% over the basic pension/ basic family pension as admissible under Tripura State Civil Services (Revised Pension) Rules, 2017 read with its 1st Amendment, 2018 with effect from 01-12-2022, to the State Government pensioners and family pensioners. With the release of this installment, total quantum of Dearness Relief payable to the State Government pensioners and family pensioners with effect from 01-12-2022 shall stand at 20 % (8% + 12 %) over the Basic pension/ family pension, as the case may be.

2. The payment on account of Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

3. The Pension Disbursing Authorities including Public Sector Banks handling disbursement of pension/ family pension to the State Government Pensioners / Family Pensioners are authorized to calculate and disburse Dearness Relief at the above rate and manner in each individual case from 01-12-2022.

4. The expenditure on payment of Dearness Relief on pension/ family pension to the State Government Pensioners / Family Pensioners respectively shall be debitable to the Major Head '2071-Pension and other Retirement Benefits'.


(A. Dewanjee)

Deputy Secretary to the
Government of Tripura
Finance Department

To
Secretary In-charge of all Department / All Heads of Department.

Continued on page-

Copy forwarded to :

1. The Secretary to the Hon'ble Governor of Tripura, Agartala.
2. The Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Tripura, Agartala.
3. The PS/PA to the Hon'ble Dy. Chief Minister, Tripura, Agartala.
4. The PS/PA to all Hon'ble Ministers, Tripura.
5. The PS/ PA to the Chief Secretary, Tripura, Agartala.
6. The Secretary, Tripura Legislative Assembly, Agartala.
7. The Secretary, T.P.S.C., Agartala.
8. The Accountant General (A&E), Tripura, Agartala with 5(five) ink signed copies.
9. The Accountant General (Audit), Tripura, Agartala with 5(five) ink signed copies.
10. The Accountant General of all States, -----
11. The Addl. Secretary, GA(C&C) Department, Agartala. This has reference to the Memorandum No.F.1(9)-GA(CAB)/2021(P)-A dated 27-12-2022.
12. The Principal Chief Accountant, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government & Bank Accounts Administration, Division C & 7 Bandra Kurla Complex, 2nd Floor, Post Bag No.1843, Bandra (E), Mumbai-400 051.
13. The Chief Manager, Centralised Pension Processing Centre, State Bank of India, Zonal Office, Sethi Trust Building, Unit - I, 6th Floor, Bhangarh, Guwahati, Assam - 781005 for information and with request to arrange for sending a copy to each of their Bank Branches within the State of Tripura.
14. The General Manager, (Accounts, Govt. Transaction & IBR), Punjab National Bank, United Tower, Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001 for information and with request to arrange for sending a copy to each of their Bank Branches within the State of Tripura.
15. The Assistant General Manager, UCO Bank, Operation & Services Department, 3 & 4 DD Block, Sector - I, Salt Lake, Kolkata - 700064 for information and with request to arrange for sending a copy to each of their Bank Branches within the State of Tripura.
16. The Regional Manager (Urban), State Bank of India, Palace Compound, Jagannathbari Road, Agartala for information and with request to arrange for sending a copy to each of their Bank Branches within the State of Tripura.
17. The Regional Manager (Rural), State Bank of India, Bijoy Kumar Chowmuhani, Agartala for information and with request to arrange for

sending a copy to each of their Bank Branches within the State of Tripura.

18. The Regional Manager, Punjab National Bank, Circle Office, Lakshminarayanbari Road (Near Durgabari), Agartala for information and with request to arrange for sending a copy to each of their Bank Branches within the State of Tripura.
19. The Chief Manager, UCO Bank, Central Road, Kaman Chowmuhani, Agartala for information and with request to arrange for sending a copy to each of their Bank Branches within the State of Tripura.
20. The Joint Secretary, Establishment-I Branch, Finance Department, Agartala.
21. All Treasury / Sub-Treasury Officers, Tripura_____
22. The Joint Director, IT for uploading the same in the State Government Website.
23. The Web-Administrator, Finance Department for uploading the same in the web-portal of Finance Department.